



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2643]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 10, 2019/श्रावण 19, 1941

No. 2643]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10, 2019/SHRAVANA 19, 1941

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2019

का.आ. 2903(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) जनशक्ति विकास योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात योजना-कहा गया है) के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को फीस की प्रतिपूर्ति को प्रशासित करता है;

उपरोक्त योजना के अधीन वर्तमान योजना दिशानिर्देशों में यथापरिभाषित मानदण्डों को पूरा करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) के अभ्यर्थियों को नियोजनीयता, उद्यमशीलता के सृजन हेतु और देशभर में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में गतिविधियों को प्रारंभ और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे के आधार पर संकलित पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके फायदा कहा गया है) उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को वित्तीय सहायता दी गई है।

उपरोक्त योजना में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्बलित हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1) योजना के अधीन फायदे प्राप्त करने के पात्र प्रत्येक फायदाग्राही के लिए आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन कराना अपेक्षित होगा।

2) योजना के अधीन फायदे प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे प्रत्येक फायदाग्राही, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी भी आधार के लिए अपना नामांकन नहीं किया है, को प्रशिक्षण प्रारंभ होने के तीस दिन के भीतर आधार नामांकन के लिए आवेदन देना होगा बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) से संपर्क कर सकते हैं।

3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय से अपेक्षित है कि वह अभी तक आधार के लिए नामांकित न किए गए फायदाग्राहियों या ऐसे फायदाग्राहियों जिनके संबंधित ब्लॉक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र नहीं है, को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा : परन्तु आधार जारी किए जाने के समय तक योजना के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में ऐसे फायदाग्राहियों को फायदा दिया जाएगा अर्थात्:

(क) (i) यदि नामांकन किया गया है तो फायदाग्राही की आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज:

(i) बैंक पासबुक या फोटो युक्त डाकघर पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड; या (iv) स्थायी खाता संख्यांक कार्ड; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1998 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (iv) एमजीएनआरईजीएस (मनरेगा) कार्ड; या (vii) किसान फोटो पासबुक, या (vii) पासपोर्ट; या (viii) तहसीलदार या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी, ऐसे सदस्य के फोटो सहित पहचान प्रमाणपत्र; या मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु उपर्युक्त दस्तावेज को विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा चेक किया जाएगा।

2. योजना के अधीन, फायदाग्राहियों के लिए सुविधाजनक और बाधा रहित फायदा प्रदान करने हेतु मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक प्रबंध करेगा, अर्थात्:-

1) योजना के अधीन फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार करके आधार संख्यांक की अपेक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन्हें यह सलाह दी जा सकेगी कि वे अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में नामांकन करवाएं यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

2) यदि योजना के अधीन फायदाग्राही ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे अपने आसपास के क्षेत्र में नामांकन केन्द्रों की गैर उपलब्धता के कारण आधार में नामांकन नहीं करा पा रहे हैं, तो मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और फायदाग्राही से अनुरोध किया जा सकेगा कि वे मंत्रालय या कार्यान्वयन एजेंसी के नामनिर्दिष्ट अधिकारियों के पास या इस प्रयोजन हेतु तैयार वेब पोर्टल के माध्यम से अपने नाम, पते, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य विवरण देकर आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें।

(3) उस दशा में, जहां योजना के अधीन फायदाग्राही, जिन्होंने आधार के लिए नामांकन करवाया है, किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आधार संख्या प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से

यूआईडीएआई के नामांकन के माध्यम से "मेरा आधार खोजें" की सुविधा प्रदान करेगा और सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सुकर बनाकर ग्राहक को अद्यतन करेगा और आधार साझा करने, परिचालित करने या प्रकाशित करने के संबंध में उक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए फायदाग्राही का आधार खोजने के लिए प्रचालक को नाम, पता, मोबाइल नम्बर, अंगुलीछाप और अन्य ब्यौरे देकर उसकी सहायता से अपना आधार खोजने का अनुरोध किया जा सकेगा।

3. सभी मामलों में, जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों का आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो अपवादिक स्थितियों से निपटने के लिए निम्नलिखित तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थात्:-

(क) अंगुलीछाप की गुणवत्ता खराब होने के मामले में, अधिप्रमाणीकरण के लिए आइरिस स्कैन सुविधा अपनाई जाएगी जिसके द्वारा मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से निर्बाध ढंग से फायदों के परिदान के लिए अंगुलीछाप स्कैनर के साथ आइरिस स्कैनर हेतु उपबंध करता है;

(ख) फायदाग्राहियों के रूप में वरिष्ठ नागरिकों के अंगुलीछाप और आइरिस अधिप्रमाणीकरण में यदि कठिनाई आती है तो उनके चेहरे के अधिप्रमाणन का प्रयोग किया जाएगा। मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन फायदाग्राहियों, जिनके अधिप्रमाणीकरण के अन्य तरीके विफल हो जाते हैं, जहां कहीं भी साध्य है, चेहरे के अधिप्रमाणीकरण के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ग) अंगुलीछाप या आइरिस या चेहरे के अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन असफल रहने के मामले में जहां कहीं भी व्यवहार्य और ग्राह्य है, सीमित समय की वैधता के साथ आधार ओटीपी या टीओटीपी यथास्थिति, द्वारा अधिप्रमाणन को प्राथमिकता दी जाएगी;

(घ) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या ओटीपी अधिप्रमाणन संभव नहीं है वहां भौतिक रूप से आधार पत्र के अधिप्रमाणीकरण के आधार पर फायदे दिए जा सकते हैं जिसकी प्रामाणिकता का अधिप्रमाणीकरण आधार पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए मंत्रालय अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आधार पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए ई-आधार सेवा प्रदायगी बिंदु पर क्यूआर कोड रीडर उपलब्ध कराएगा जिसके माध्यम से ऑफलाइन ढंग से आधार कार्ड की प्रामाणिकता का अधिप्रमाणीकरण किया जा सकता है। इस क्यूआर कोड को प्राथमिक रूप से यूआईडीएआई द्वारा विकसित सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर के जरिए पढ़ा जाए चूंकि यह कार्ड धारक के अंकीय रूप से हस्ताक्षरित ब्यौरा उपलब्ध कराता है। ऐसे सभी मामलों में इसी प्रयोजन से तैयार किए गए अपवादिक स्थितियों से निपटने के लिए रजिस्टर में संव्यवहार को विधिवत रूप से अभिलिखित करने के पश्चात फायदे उपलब्ध कराए जा सकते हैं जिसे मंत्रालय द्वारा आवधिक रूप से पुनरावलोकित और लेखापरीक्षित किया जाए। इन रजिस्ट्रों की देखरेख और आवधिक निरीक्षण अपवादिक स्थितियों से निपटाने के लिए तंत्र के अनिवार्य घटक होंगे।

4. यह अधिसूचना जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा.सं. एल-14013/6/2018-एचआरडी]

जयदीप कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2019

S.O. 2903(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Electronics and Information Technology (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Fee Reimbursement to Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the

Manpower Development Scheme (hereinafter referred to as the Scheme), implemented through National Institute of Electronics and Information Technology (hereinafter referred to as the Implementing Agency) under Ministry of Electronics and Information Technology;

And whereas, under the aforesaid Scheme, financial assistance is given to the Implementing Agency to provide free of cost training (hereinafter referred to as the benefit) to the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (hereinafter referred to as the beneficiaries), who meet the criteria as defined in the extant Scheme guidelines, on the National Skills Qualifications Framework complied courses for the employability, entrepreneurship creation and to initiate and promote activities in Information and Communications Technology across the country;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) Every beneficiary eligible for receiving the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Every beneficiary desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment within thirty days of the commencement of the training, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the beneficiary, benefit under the Scheme shall be given to such beneficiaries, subject to production of the following documents, namely:-

- (a) (i) if enrolled, Aadhaar Enrolment ID slip of the beneficiary; or
- (ii) a copy of request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (b) any of the following documents:

(i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter identity card; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number Card; or (v) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) MGNREGS Card; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) Passport; or (ix) Certificate of Identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agency shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Ministry or Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

(3) In case, the beneficiaries under the Scheme who have enrolled for Aadhaar, however, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, the Ministry through its Implementing Agency shall provide "Search My Aadhaar" facility through UIDAI's Enrolment and Update Client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to search their Aadhaar in assisted mode by giving their

name, address, mobile number, finger-prints and other details, with the operator required to search beneficiary's Aadhaar, subject to the provisions of the said Act and regulations made thereunder, with respect to restriction on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry through its Implementing Agency make provisions for IRIS scanners along with fingerprint scanners for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of difficulty in fingerprints or IRIS authentication of senior citizens of the beneficiaries, face authentication shall be used. The Ministry through its Implementing Agency shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those beneficiaries whose other modes of authentication fail;

(c) in case of biometric authentication through fingerprints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar OTP or TOTP with limited time validity, as the case may be, shall be preferred;

(d) in all other cases where biometric or OTP authentication is not possible, benefits may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter. For this, the Ministry through its Implementing Agency shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar Letter on E-Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar Card in offline manner. This QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by UIDAI as it provides digitally signed details of Aadhaar Holder. In all such cases the benefits may be provided after duly recording the transaction in the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the Ministry. Maintenance of these registers and periodic inspection will be an essential component of exception handling mechanism.

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the State of Jammu and Kashmir.

[F.No. L-14013/6/2018-HRD]

JAIDEEP KUMAR MISHRA, Jt. Secy.